जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 46 संख्याः 112 प्रभात बीकानेर, बुधवार 13 नवम्बर, 2024 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रू.

महाराष्ट्र में भाजपा और कांग्रेस ने ''रेवड़ियों'' की बरसात की

किसी ने नहीं मानी, रेवड़ी कल्चर पर रोक के लिए रिजर्व बैंक की सलाह

- श्रीनन्द झा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 12 नवम्बर। चुनावों से मुफ्त सुविधाएं देना अर्थात ''रेवड़ी कल्चर'' पर सुप्रीम कोर्ट की कठोर सलाह का महाराष्ट्र में न तो महाविकास अघाड़ी पर कोई असर हुआ है ना ही सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन पर। भाजपा ने महिलाओं को प्रतिमाह 21,000 रुपये देने की घोषणा की है और कांग्रेस महिलाओं को प्रतिमाह तीन हजार रुपये देना का वादा किया है। भाजपा ने दस लाख विद्यार्थियों प्रतिमाह दस हजार रु. देने तथा 25 लाख रोजगार सृजित करने का वायदा किया है।

कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं चार हजार रु. का भत्ता देने की घोषणा की है वहीं भाजपा ने राज्य पुलिस में 25,000 महिलाओं को नौकरी देने का वादा किया है। भाजपा के अन्य वादों के बिजली के बिल में 30 प्रतिशत की कटौती, वृद्धावस्था पेंशन 1500 से बढ़ाकर 2100 करने ओर किसान सम्मान योजना में किसानों को सालाना बारह हजार से बढ़ाकर पन्द्रह हजार रु. देने की घोषणा की है और आंगनबाड़ी और आशा सहयोगिनियों को 15,000 और बीमा बतौर मासिक मानदेय दिए जाने का वादा किया गया है। दूसरी ओर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने तीन लाख रु. तक का कर्ज माफ करने और 6 एल.पी.जी. सिलैण्डर 500 रु की रेट पर देने का वायदा किया साथ ही शिक्षित बेरोजगारों का 4,000 रु मासिक देने की घोषणा की है।

- भाजपा ने महिलाओं को प्रति माह 21 सौ रूपये देने का वादा किया तो कांग्रेस ने 3 हजार रुपये देने की घोषणा की।
- भाजपा ने 10 लाख विद्यार्थियों को 10 हजार रू. प्रतिमाह भत्ता देने व 25 लाख रोजगार सृजित करने की घोषणा की है, वहीं, कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं को चार हजार रू. प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया।
- इसके अलावा भाजपा ने बिजली के बिल में 30 प्रतिशत की कटौती, आंगनबाड़ी व आशा सहयोगियों के मानदेय में वृद्धि का वादा किया।
- कांग्रेस ने 500 रू. की दर पर साल में 6 रसोई गैस सिलैंडर देने की घोषणा की है।
- ज्ञातव्य है कि, जून में आई एक रिपोर्ट में आर.बी.आई. ने कहा था कि राज्य सरकारें सब्सिडी का बढ़ा हिस्सा मुफ्त सुविधाओं के रूप में दे रही हैं।

जून की एक रिपोर्ट में, आर. बी. आई. ने सी. ए. जी. के उपलब्ध डेटा का हवाला देते हुए कहा था कि सब्सिडी, जो 2020-21 में 11.2 प्रतिशत थी, 2021-22 में बढ़कर 12.9 प्रतिशत हो गई है, जबकि 2019-20 में ये कम हो गई थी। रिपोर्ट बताती है कि कुल राजस्व व्यय में सब्सिडीज का हिस्सा, जो 2019-20 में 7.8 प्रतिशत था, 2021-22 में बढ़कर 8.2 प्रतिशत हो गया है। रिपोर्ट में झारखंड, केरल, ओडिशा, तेलंगाना तथा उत्तर प्रदेश का उल्लेख ऐसे राज्यों के रूप में किया गया है, जिनमें पिछले तीन सालों में सब्सिडीज में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाई गई है। गुजरात, पंजाब और चंडीगढ़ भी ऐसे राज्यों के रूप में दर्शाये गये हैं, जहां सब्सिडीज पर उनके राजस्व व्यय का 10 प्रतिशत से अधिक खर्च हुआ है। रिपोर्ट आगे कहती है कि हाल ही के दौर में, राज्य सरकारों ने अपनी सब्सिडीज का एक हिस्सा रेवड़ियों के रूप में बांटना शुरू कर दिया है।

तकनीकी खराबी के कारण वापस लौटा राहुल का विमान

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 12 नवम्बर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मंगलवार को महाराष्ट्र के बुलढ़ाना जिले के चिखली कस्बे की अपनी चुनावी सभा निरस्त करनी पड़ी, क्योंकि उनकी फ्लाइट में कोई तकनीकी खराबी पैदा हो गई थी तथा पायलट उसे दिल्ली वापस ले आया।

उन्हें दिन में 12.30 बजे कांग्रेस प्रत्याशी राहुल बोन्द्रे के समर्थन में जनसभा को सम्बोधित करना था। उन्होंने जनसभा के निरस्तीकरण के बारे में एक वीडियो बयान जारी किया तथा कहा कि वे वहां सोयाबीन तथा कपास उत्पादक किसानों से मिलने के लिये उत्सुक थे।

- राहुल महाराष्ट्र में चिखली जनसभा में नहीं पहुंच सके।

लेकिन राहुल गांधी ने गोदिया में अपनी दूसरी रैली में पहुंचने में कामयाब रहे।

अपने बयान में, उन्हंने चिखली के मतदाताओं को आश्वस्त किया कि इंडिया ग्रुप की सरकार वहां के लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेगी।

सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई के मौखिक आवेदन अब स्वीकार नहीं होंगे

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने प्रक्रिया सम्बंधी पहले निर्णय में यह निर्देश दिया

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 12 नवम्बर। अब तक चली आ रही परम्परा से अलग हटते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने मुकदमों की अर्जेन्ट लिस्टिंग तथा सुनवाई के मौखिक निवेदन पर मंगलवार को रोक लगा दी। इसमें पहले से सूचीबद्ध मामलों को डिलीट न किये जाने का मौखिक निवेदन भी शामिल है।

अदालत की कार्यवाही की प्रक्रिया के संबंध में लिए गये अपने पहले निर्णय में, मुख्य न्यायाधीश पद का कार्य-भार संभालने दूसरे दिन ही मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जोर देते हुए कहा कि अब दायर होने वाले नये केसों को तत्काल सूचीबद्ध किये जाने तथा उनकी सुनवाई किये जाने के मौखिक निवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। इनमें वे पुराने केस भी शामिल होंगे, जिन पर अभी तक विचार नहीं हुआ है। अब ऐसे निवेदनों के लिए ई-मेल या लिखित प्रार्थना पत्रों का ही रास्ता अपनाना होगा तथा उनमें मुकदमे की शीघ्र लिस्टिंग एवं सुनवाई के लिए कारण देने होंगे।

- उन्होंने कहा कि नए केसों को तत्काल सूचीबद्ध करने के आदेश ई-मेल या लिखित पर्ची पर ही स्वीकार किए जाएंगे, जिसमें यह बताना होगा कि त्वरित सुनवाई करना क्यों जरूरी है?
- ज्ञातव्य है कि, रिटायर्ड सी.जे.आई. डी.वॉय. चंद्रचूड के कार्यकाल में मामलों को त्वरित सुनवाई के लिए लिस्ट करने के लिए ई-मेल से आवेदन भेजने के लिए कहा गया था, पर तब भी कुछ मामलों, जैसे भवन तोड़ने या गिरफ्तारी की संभावना होने पर, न केवल केस की त्वरित सुनवाई होती थी, बल्कि इसमें सम्बंधित पक्ष को राहत भी दी गई थी।
- पूर्व चीफ जस्टिस स्व. एस.एच. कपाड़िया के कार्यकाल, 2 मई 2010 से 28 सितम्बर 2012 तक, के दौरान केस की त्वरित लिस्टिंग के लिए मौखिक आवेदन देना स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया गया था पर यह परम्परा अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

मुख्य न्यायाधीश ने मंगलवार को अदालत की कार्यवाही के प्रारम्भ में कहा, ''अब लिखित या मौखिक निवेदन बंद। केवल ई-मेल या लिखित स्लिप। अर्जेन्सी के कारणों का ही उल्लेख करें।''

याचिकाकर्ताओं को इन संदेशों, पत्रों में अपने निवेदन की अर्जेन्सी के कारण स्पष्टतः बताने होंगे।

अभी-अभी सेवानिवृत्त हुए मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चन्द्रचूड़ के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रामगढ़ के अलावा बाकी सीटों पर कांग्रेस खतरे में

सलूम्बर, झुंझनूं, देवली, उनियारा में निर्णय निर्दलीयों के हाथ में, दौसा व रामगढ़ में सीधा मुकाबला

जयपुर, 12 नवम्बर। राजस्थान में सात विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान है और मतदान से पहले उभरी तस्वीर में कांग्रेस इस बार तीन सीटों पर तीसरे नंबर पर संघर्ष करती नज़र आ रही है। एक सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा और निर्दलीय के बीच सिमट गया है। दो सीटों पर बाप और भाजपा के बीच में मुकाबला नज़र आ रहा है। रामगढ़ को छोड़कर बाकी सीटों पर कांग्रेस को इस बार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

राजस्थान की सात विधानसभा सीटों में से देवली - उनियारा सीट पर मतदान से ठीक पहले उभरी तस्वीर में मुख्य मुकाबला निर्दलीय नरेश मीणा और भाजपा के राजेन्द्र गुर्जर के बीच दिख रहा है। कांग्रेस के कई नेताओं के दौरों के बावजूद, स्थानीय जनता और खुद कांग्रेसजनों ने भाजपा से आए मीणा की उम्मीदवारी को दिल से नहीं स्वीकारा है और यही कारण है कि यहां कांग्रेस बेहद कमजोर नजर आ रही है। दौसा में डॉ किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा और कांग्रेस के डी.डी. बैरवा के बीच सीधा मुकाबला है,लेकिन ब्राह्मण नेताओं का झुकाव विप्र पंचायत के बाद भाजपा के पक्ष में जाने से भाजपा को फायदा मिलता दिख रहा है। भाजपा का परंपरागत वोट बैंक भी उसके साथ नजर आ रहा है।

दौसा में स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सत्ता के साथ रहेंगे, तो 4 साल तक विकास के काम हो पाएंगे और विपक्ष के साथ गए तो 4 साल का नुकसान हो सकता है। यह बात भी भाजपा के लिए फायदे का सौदा बन गई है। दौसा में कांग्रेस के स्थानीय नेता प्रचार में तो नजर आ रहे हैं लेकिन दिल दिमाग से वो पार्टी के साथ नजर नहीं आ रहे।

रामगढ़ विधानसभा सीट की बात करें तो स्पष्ट रूप से सहानुभूति कांग्रेस उम्मीदवार आर्यन जुबेर के साथ दिखाई पड़ रही है। वहीं, जातिगत समीकरण भी कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहे हैं। हालांकि, भाजपा के सुखवंत सिंह के पक्ष में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दो बार किए गए दौरे और अन्य नेताओं के प्रयासों के कारण भाजपा टक्कर देने में तो कामयाब हो गई है, लेकिन थोड़ा पीछे छूटती नजर आ रही है।

झुंझुनू विधानसभा सीट का उपचुनाव पूरी तरह से निर्दलीय राजेन्द्र गुढ़ा पर टिका है। गुढ़ा को मिलने वाले वोट ही तय करेंगे कि यहां पलड़ा किसके पक्ष में झुकेगा। यहां कांग्रेस के उम्मीदवार अमित ओला को परिवारवाद के आरोप के चलते विरोध झेलना पड़ रहा है। हालांकि भाजपा में भी भितरघात तो है, लेकिन स्पष्ट रूप से बागी सामने नहीं होने का फायदा राजेन्द्र भामू को मिल रहा है। यहां राजेन्द्र गुढ़ा जिस तरह की भीड़ जुटाते रहे हैं, अगर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- चौरासी सीट पर राजकुमार रोत की बाप पार्टी हावी, खींवसर में इस बार कांग्रेस व भाजपा के बागी प्रत्याशी नहीं होने से हनुमान बेनीवाल का गढ़ खतरे में नजर आ रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने अबुबकर की मैडिकल रिपोर्ट मांगी

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 12 नवम्बर। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को ऑफ इंडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) से ई.अबूबकर की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पी.एफ. आई.) के पूर्व चेयरमैन अबूबकर ने मेडिकल आधार पर जमानत के लिये आवेदन किया है।

- मैडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट प्रतिबंधित संगठन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पूर्व प्रमुख अबु बकर की जमानत याचिका पर फैसला करेगा।

न्यायमूर्ति एम.एम. सुन्द्रेश तथा अरविन्द कुमार की बैंच ने निर्देश दिये कि अबूबकर को दो दिन के अंदर एम्स ले जाया जाये तथा विधिवत भर्ती करने के बाद के चार दिन के अंदर, एक-इन-डोर मरीज के रूप में उसकी विस्तृत जांच की जाये। बैंच ने एम्स के निदेशक से भी कहा है कि वे उसकी जांच पूरी होने के तीन दिन के अंदर अदालत में उसकी रिपोर्ट पेश करें।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या सनसनीखेज खुलासा कर खुद को संकट में डाल लिया है अजित पवार ने?

राजनैतिक हल्कों में चर्चा है कि अजित पवार ने यह खुलासा शरद पवार को घेरने के लिए किया था पर उनका दांव उलटा पड़ गया है

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 12 नवम्बर। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने इस रहस्योद्घाटन से बरैया के छत्ते को छेड़ दिया लगता है, ''पांच साल पहले'' भारतीय जनता पार्टी तथा अविभाजित नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एन.सी.पी.) के बीच हुई महत्वपूर्ण मीटिंग में गौतम अडाणी भी मौजूद थे।

अजीत, जो इस समय सत्तारूढ़ ''महायुति'' गठबंधन का हिस्सा है, उस घटनाक्रम का जिक्र कर रहे थे, जो कथितरूप से सुबह जल्दी होने उस शपथ ग्रहण समारोह से पहले घटित हुआ था। इस समारोह में भाजपा नेता देवेन्द्र फडनवीस ने मुख्यमंत्री पद की, तथा स्वयं उन्होंने (तत्कालीन अविभाजित एन.सी.पी. का हिस्सा) उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।

अजीत पवार ने न्यूज वेबसाइट ''द न्यूज़ मिनट' को दिये एक इन्टरव्यू में कहा, क्या आपको नहीं मालूम? यह घटना 5 साल पहले की है। सबको मालूम है कि वह मीटिंग कहां हुई थी। सभी कहां मौजूद थे। मैं आपको फिर से बताता हूं। वहां अमित शाह थे, वहां गौतम अडाणी थे, वहां प्रफुल्ल पटेल थे, वहां देवेन्द्र फडनवीस थे, वहाँ अजीत पवार थे, वहां पवार थे, वहां पवार साहब थे, उन्होंने कहा कि एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने वहीं किया, जो उनके नेता (शरद पवार) ने कहा था।

- अजित पवार ने कहा था कि 5 साल पहले अविभाजित एन.सी.पी. और भाजपा के बीच गठबंधन को लेकर जो बैठक हुई थी उसमें शरद पवार, अमित शाह, वे खुद और गौतम अडाणी भी मौजूद थे।
- पवार के इस खुलासे से यह सवाल उठ रहा है कि विभिन्न दलों के साथ डीलिंग में क्या गौतम अडाणी भाजपा के मध्यस्थ बनते हैं।
- अजीत पवार के इस बयान से गौतम अडाणी और भाजपा की सांठ-गांठ के कांग्रेस के आरोप की भी पुष्टि होती है।
- चर्चा है, कि अजीत के इस बयान से भाजपा के भीतर भारी नाराज़गी है।

अजीत का विद्रोह 80 घंटे तक चला था, क्योंकि शरद पवार ने निर्णय लिया था कि वे उन्हें (समर्थन) नहीं देंगे। इसके बाद, जूनियर पवार के साथ गये अधिकांश विधायक मूल पार्टी में लौट गये थे। इस घटना के चन्द रोज बाद, अविभाजित एन.सी.पी., शिव सेना तथा कांग्रेस ने मिलकर महाराष्ट्र में महा विकास (एम.वी.ए.) सरकार बना ली थी।

यह पूछे जाने पर, कि उनके चाचा शरद पवार ने ''क्रासओवर'' क्यों नहीं किया था, अजीत ने कहा, ''शरद पवार इस प्रकार के व्यक्ति हैं, जिसकी सोच के बारे में कभी भी भविष्यवाणी नहीं जा सकती। दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, जो उनके बारे में भविष्यवाणी कर सके। यह काम तो हमारी चाची तथा सुप्रिया (उनकी पुत्री) भी नहीं कर सकती।''

जब सीनियर पवार के नेतृत्व वाली एन.सी.पी.-एस.पी. की सुप्रिया सुले से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुझे ऐसी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या राहुल गाँधी से बड़ी जीत मिलेगी प्रियंका को वायनाड में?

प्रियंका गाँधी की जीत तो तय सी है, चर्चा बस जीत के मार्जिन को लेकर ही चल रही है

-लक्ष्मण वेंकट कूची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 नवंबर। जब तक आप यह खबर पढ़ेंगे, तब तक वायनाड के 14 लाख मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान शुरू कर चुके होंगे, और जमीनी रिपोर्ट के अनुसार, पूरी संभावना है कि कुछ सप्ताह पूर्व अपने भाई राहुल गाँधी द्वारा खाली की गई सीट से जीत कर प्रियंका गाँधी लोकसभा से प्रवेश करेंगी।

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि प्रियंका गाँधी का जीत का अंतर कितना होगा, क्या वे अपने भाई राहुल गाँधी की तुलना में अधिक बहुमत से जीतेंगी।

राहुल दो बार वायनाड से जीत चुके हैं, पर इस बार वे रायबरेली लोकसभा सीट से भी जीते तथा उन्होंने वायनाड की सीट खाली करने और अपनी बहन को वहाँ से चुनाव लड़वाने का निर्णय लिया। इसका आशय यह था कि उत्तर तथा दक्षिण भारत, दोनों जगह गाँधी परिवार का कोई प्रतिनिधि हो। ज्ञातव्य है कि हिन्दी भाषी क्षेत्र की तुलना में कांग्रेस पार्टी की स्थिति दक्षिण भारत में बेहतर है।

बुधवार सुबह सात बजे, वायनाड के करीब एक हज़ार मतदान केन्द्रों पर वोटिंग शुरू होगी।

- प्रियंका गाँधी वायनाड में जहाँ भी गई हैं, या जहाँ नहीं जा पाई हैं, जनता में उन्हें लेकर भारी उत्साह दिख रहा है।
- भाजपा और वामपंथी दल बार-बार यही कह रहे हैं कि राहुल गाँधी ने वायनाड को धोखा दिया है और बड़ी जीत मिलने के बाद भी उन्होंने यह सीट छोड़ दी।
- वायनाड से प्रियंका गाँधी के खिलाफ भाजपा की नव्या हरिदास और वाममोर्चा के सत्यन मोकरी मैदान में हैं।

मतों की गिनती, महाराष्ट्र एवं झारखंड विधानसभा चुनावों तथा अन्य राज्यों के उपचुनावों के साथ 23 नवंबर को होगी।

प्रचार के दौरान, प्रियंका गाँधी ने काफी विस्तार से उस प्यार और स्नेह की बात की, जो वायनाड की जनता ने उनके भाई को दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि केरल के इस शहर के लोग उन्हें भी उतना ही या और अधिक प्यार व स्नेह देंगे। उन्होंने उस प्राकृतिक आपदा को याद किया, जो हाल ही में वायनाड के लोगों ने झेली थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे तथा अनेक संपत्तियाँ तहस-नहस हो गई थीं।

प्रियंका गाँधी का विरोध कर रहे, लैफ्ट डैमोक्रैटिक फ्रंट (एल.डी.एफ.) के सत्यम मोकेरी एवं भाजपा की नव्या हरिदास आशा कर रहे हैं कि चुनावी अनुभव की कमी प्रियंका के विरुद्ध जा सकती है। इसके अलावा, वाम व दक्षिण पंथी, दोनों उम्मीदवारों ने इस बात पर जोर दिया कि 2019 में 4.3 लाख वोटों से जीतने के बाद भी कैसे राहुल गाँधी ने इस निर्वाचन क्षेत्र की अनदेखी की है। पिछले चुनावों में राहुल गाँधी 3.4 लाख वोटों के अंतर से जीते थे। प्रियंका जहाँ भी गईं या नहीं गईं, उन्हें उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया मिली है। चुनाव प्रचार सोमवार शाम को समाप्त हो गया।

चुनाव अभियान के दौरान, प्रियंका गाँधी ने कहा, ''मैं एक योद्धा हूँ और हर मंच पर वायनाड के लोगों के लिए लड़ूंगी।''वायनाड लोकसभा सीट के अंतर्गत, वायनाड, कोझीकोड और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उपभोक्ता आयोग ने जेडीए पर 5.21 लाख हर्जाना लगाया

जयपुर, 12 नवंबर। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने सीकर रोड स्थित रजत विहार योजना में परिवादी को 16 साल पहले आवंटित भूखंड का पट्टा व कब्जा नहीं देने को सेवा दोष करार दिया है। वहीं, जेडीए व जोन-12 उपायुक्त पर 5.21 लाख रुपए हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही, जेडीए को एक महीने में जहां खाली भूखंड हो, उसका कब्जा परिवादी को देने अन्यथा जमा राशि 6,88,532 रुपए 18 प्रतिशत ब्याज सहित परिवादी को लौटाने के लिए कहा है। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना व सदस्य

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सीकर रोड पर रजत विहार योजना में 16 साल पहले आवंटित भूखंड की राशि लेकर भी परिवादी को कब्जा नहीं दिया।

प्रदेश की 23 हजार खानों की वैधता 31 मार्च तक बढ़ी

जयपुर, 12 नवंबर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के 23 हजार खान संचालकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने इनकी खनन वैधता को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया है। अदालत ने कहा है कि जो खनन पट्टा धारक जिला स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण से मंजूरी लेकर चल रहे हैं, वे तीन सप्ताह के भीतर राज्य स्तरीय प्राधिकरण में पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदन करें। चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया (सी.जे.आई.) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्राधिकरण की मंजूरी वालों को तीन सप्ताह में राज्य स्तर पर आवेदन करने को कहा।